

भारत का वाजपेश The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ६६]

नई विस्ती, शनिवार, मार्च २०, १९७६/फाल्गुन ३०, १८९७

No. ६६]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1976/PHALGUNA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह घलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM

RESOLUTION

New Delhi, the 18th March 1976

SUBJECT.—Price structure of Synthetic Rubber.

No. N-18011/2/75-PC. I.—The 1971 Report of the Tariff Commission on the fair selling price of synthetic rubber was submitted in September, 1971. The consideration of these recommendations took considerable time as fundamental issues were raised. It was decided while accepting some of the recommendations of the Tariff Commission, to refer the matter back to the Tariff Commission for recalculation of prices taking into account escalations in costs which had occurred in the intervening period. The Commission submitted its Report to Government in May, 1975. The Commission in its Report has mentioned the pros and cons of price control but has not expressed any definite opinion; it has assumed that price control would continue and has left the matter of decontrol for such action as the Government may consider necessary.

2. Having considered all aspects of the matter, Government have decided to decontrol prices of synthetic rubber for the following reasons:—

- (a) Changes in input costs are taking place frequently.
- (b) There is no price control on the products using SBR.
- (c) There is considerable disparity between the presently controlled prices of synthetic rubber and the prevailing prices of natural rubber.
- (d) The prices of various raw materials required for making SBR are not controlled with the exception of alcohol, the cost of which constitutes only about 15 per cent to 20 per cent of the total cost of production of SBR.

3. In the context of the decision taken to decontrol prices of synthetic rubber, Government do not accept the recommendations of the Tariff Commission in this regard.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India extraordinary.

B. B. VOHRA, Secy.

पंद्रोलियम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1976

विषय.—सिन्थेटिक रबड़ की मूल्य संरचना।

सं० ए० १८०११/२/७५-पैद्रोलियम-I.—सिन्थेटिक रबड़ को उचित मूल्य पर बेचने के बास्ते टरिफ़ आयोग की 1971 की रिपोर्ट सितम्बर, 1971 में प्रस्तुत की गई थी। चूंकि सौलिक प्रश्न उठाए गए थे इसलिए इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए काफी समय लग गया। टरिफ़ आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार करते हुए यह निर्णय हुआ था कि जो खर्च इस अवधि में हुआ था उस खर्च में हुए अत्यधिक वृद्धि का हिसाब रखते हुए मूल्यों को पुनः हिसाब लगाने के बास्ते वह मामला टरिफ़ आयोग को पुनः भजने के लिए कहा गया था। आयोग ने मई 1975 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की थी। आयोग ने मूल्य नियन्त्रण की अभियास्यों तथा बुराइयों का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है किन्तु उस ने कोई नियन्त्रित मत अभिव्यक्त नहीं किया है; यह समझा जाता है कि मूल्य नियन्त्रण चलता रहेगा और इस प्रकार की कार्रवाई जिसे सरकार आवश्यक समझती हो, के लिए मूल्य नियन्त्रण समाप्त करने का मामला सरकार पर छोड़ दिया है।

2. उस मामले के समस्त पहलुओं पर विचार करने के बाद, सरकार निम्नलिखित कारणों से सिन्थेटिक रबड़ का मूल्य नियन्त्रण समाप्त करने का निर्णय कर चुकी है।

- (क) निवेश लागतों में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है।
- (ख) एस बी आर का प्रयोग करने वाले उत्पादों पर कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं है।
- (ग) इस समय सिन्थेटिक रबड़ के नियन्त्रित मूल्यों और स्वाभाविक रबड़ के प्रचलित मूल्य के बीच काफी अन्तर है।
- (घ) जिस एल्कोहॉल की लागत एस बी आर की उत्पादन का कुल लागत का लगभग 15% से 20% तक होती है, उस एल्कोहॉल को छोड़ कर एस बी आर का निर्माण करने के लिए अपेक्षित विभिन्न कच्चे माल के मूल्यों का नियन्त्रण नहीं किया जाता है।

सिन्थेटिक रबड़ का मूल्य नियन्त्रण समाप्त किए जाने के निर्णय के सम्बन्ध में सरकार टरिफ़ आयोग की इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समस्त सम्बन्धितों को भेजी जाए और इसे भारत के असाधारण राज पत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० बी० वोहरा, सचिव।